>

Title: Regarding regularization of daily workers, casual workers, contractual workers.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairperson, about 80,000 daily-rated workers, casual workers, contractual workers, need-based workers are awaiting regularisation for the last 10 years. जम्मू-कश्मीर के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है । इनमें से 30,000 बीजेपी गवर्नमेंट ने ही भर्ती की हुई है । आज यह पोजिशन है कि उनको रेगुलर वेजेज़ नहीं मिल रहे हैं । सारे के सारे ये जो वर्कर्स हैं, वे तकरीबन सालों सड़कों पर रहते हैं । इस रेगुलराइजेशन को एक्स्पिडाइट करने की मेरी गुज़ारिश है । इसके अलावा, जो नई तालीमी पॉलिसी है, उसके तहत जो भी इनके लक्ष्य है, किसी कॉलेज में कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है । उनकी जो तादाद है, उन सारे की अकादमिक सेशन बेस्ड नियुक्ति होती है, वे रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं । इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी बड़ी पीड़ा है, हजारों के करीब कुनबे मुतास्सिर हैं । वैसे तो यह सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से था, वह भी यहाँ पर तशरीफ़ रख देते, अभी यहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं । ये जो सारे मुलाज़िम कॉन्ट्रैक्ट रीलेटेड वर्कर्स हैं, इनकी रेगुलराइजेशन का कोई प्रोविज़न बनाइए, कोई प्लान बनाइए, कोई स्कीम बनाइए, ताकि इनको राहत मिले । इन पर जो निर्भर करते हैं, उनकी जो फैमिली है, उन फैमिलीज़ को भी कोई राहत मिले । उनकी एजुकेशन वगैरह की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

इसके अलावा, 15,000 के करीब हमारे मेडिकल स्टूडेन्ट्स हैं, जो एनरोल्ड हैं, पिछले साल पाँच अगस्त को कानून में परिवर्तन किया गया, फार्मसिस्ट एक्ट में तरमीम लाई गई और इनको इनेलिजिबल बनाया गया । उनको वन टाइम एग्जेम्प्शन दिया जाए । इस वक्त इन सारे इंस्टिटयूशंस में जो भी मेडिकल स्टूडेन्ट्स एनरोल्ड हैं, उनको वन टाइम एग्जेम्प्शन दिया जाए । उनको भी

फार्मसिस्ट के रूप में रेगुलराइजेशन करने के लिए अवसर दिया जाए। यही मेरी दो माँग हैं।